

अध्याय - 10

सांराश, निष्कर्ष, सुझाव एवं संभावनाएं

“प्रस्तुत अंतिम अध्याय में शोध अध्ययन विषय का सारांश, निष्कर्ष, सुझाव एवं संभावनाएं की विवेचना की गई है।”

सारांश

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत प्राचीन काल से ही सक्रिय रहा है। स्वतंत्रता के उपरांत परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, कृषि, प्रौद्योगिकी विकास आदि क्षेत्रों में हमने महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की हैं। लेकिन विज्ञान क्षेत्र में हुए विकास के बावजूद हमारी अधिकांश जनता गरीबी, भूख, प्यास, गंदगी एवं रोग की त्रासदी से मुक्ति नहीं पा सकी है। शोधार्थी का मानना है कि हमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को वास्तविकता के धरातल पर लाने की जरूरत है ताकि इसके उपयोग से हम अपने देशवासियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार ला सकें।

प्राचीन सभ्यता के उत्तराधिकारी के नाते हमें आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बहुंगी मोतियों को एक धागे में पिरोकर रखना चाहिए जिससे एक समृद्ध तथा परिपूर्ण परिदृश्य का निर्माण हो सके, एक ऐसे समाज का निर्माण हो सके जहां हर कोई भोजन, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य की देखभाल और शिक्षा जैसी जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं प्राप्त कर सके, अपने उत्थान के लिए कार्य कर सके और साथ ही मानव होने के नाते दूसरों की मदद के लिए भी आगे आ सके।

नई प्रौद्योगिकी और सूचना के सर्वभौम प्रवाह से जहां मानव की अंतहीन समस्याओं का समाधान हुआ है वहीं अतीत की संतुलकारी प्राचीन सामाजिक प्रक्रियाओं ने इस परिवर्तित वातावरण में काम करना बंद कर दिया है। समाज को नये प्रौद्योगिकीय, आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक ढांचे के अनुरूप ढालने पर ध्यान देना होगा, ताकि नई संभावनाओं का सर्वोत्तम और सार्थक उपयोग किये जा सके। नई सहस्राब्दी हमें अपनी ओर खींच रही है। पिछली शताब्दी के अंतिम दौर में ऐसी नई प्रौद्योगिकी का विस्फोट हुआ है जिसने मानव जीवन के कई पहलुओं को एक साथ प्रभावित किया। संचार और सूचना क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी के अनियंत्रित विकास ने मानव जाति के विकास के नये मार्ग प्रशस्त किये हैं। इससे वह भौगोलिक दूरी कम हो गई है जो मानव जाति के एकीकरण के मार्ग में अड़चन बनी हुई थी। समुदाय के लिए नई सूचना एवं प्रौद्योगिकी को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वातावरण के अनुरूप ढालने पर विचार करना जरूरी है ताकि उपलब्ध संभावनाओं का सर्वोत्तम और सार्थक उपयोग किया जा सके।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थ-व्यवस्था कृषि आधारित मिश्रित और औद्योगिक अर्थ व्यवस्था है। कृषि के बाद हथकरघा उद्योग एक प्रमुख रोजगारोन्मुख उद्योग है

। हथकरघा उद्योग परिवार मूलक, न्यूनतम पूंजी निवेश वाला शक्ति आधार रहित एवं पर्यावरण को हानि न पहुंचाने वाला उद्योग होने से रोजगार निर्माण योजनाओं के अंतर्गत विशेष स्थान रखता है। भारत हाथकरघा वस्तुओं के मामले में काफी समृद्ध रहा है एवं इस क्षेत्र में उसकी विरासत बहुआयामी है। प्राचीन काल में दुनिया के विभिन्न देशों में भारत से जो वस्तुएं निर्यात की जाती थीं, उनमें हाथकरघा की वस्तुओं का स्थान सबसे ऊपर था और इनमें खादी की धोती, मलमल, बनारस की कालीन आदि की ख्याति विश्व में प्रसिद्ध थी। आधुनिक तकनीकी और अत्यधिक अनुसंधान और विकास से लाभान्वित दुनिया के अन्य देशों से मिली कड़ी चुनौती के बावजूद भारतीय हाथकरघा की वस्तुओं का स्थान अब भी सर्वोपरि है। बेजोड़ हस्तकारी, उत्कृष्ट डिजाइन, मोहक स्वरूप तथा रंगों के इस्तेमाल के लिए भारतीय हस्तकार आज भी सराहे जाते हैं।

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा और रायगढ़ क्षेत्र के बुनकर (कोष्टा) समुदाय के द्वारा हाथकरघा पर उत्पादित विविध वस्त्र जन मानस पटल पर अपनी विशिष्ट छाप निरंतर बनाये हुआ है। देश के लिये विदेशी मुद्रा अर्जित करने में साधक बने अध्ययन क्षेत्र के बुनकर (कोष्टा) समुदाय की सामाजिक-आर्थिक सूचना आवश्यकता के विशेष संदर्भ में प्रस्तुत शोध अध्ययन का सारांश निम्नानुसार है :-

इस बात की कहीं भी प्रमाणित उल्लेख व जानकारी नहीं है कि रायगढ़ क्षेत्र में बुनाई कार्य कब से प्रारंभ हुआ? परंतु क्षेत्र के कोष्टा समुदाय के बुनकरों की मान्यता एवं जनश्रुति के अनुसार जब से भारत में बुनाई कार्य प्रारंभ हुआ है, तब से इस क्षेत्र में भी बुनाई कार्य प्रारंभ हुआ है, माना जा सकता है। अध्ययन क्षेत्र के बुनकर लोगों का प्रमुख व्यवसाय हथकरघा बुनाई कार्य है एवं कृषि सहायक व्यवसाय है। उनमें (कोष्टा समुदाय) प्रचलित सामाजिक मान्यताएं एवं संस्कार लगभग हिन्दू धर्म के समान ही हैं किन्तु वे देवी आराधना में विशेष आस्था रखते हैं।

रायगढ़ क्षेत्र में 13 बुनकर सहकारी समितियां अस्तित्व में हैं। संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 66% बुनकर इकाई (जिसकी संख्या 2000 है) अध्ययन क्षेत्र में विद्यमान है। क्षेत्र के बुनकर वर्षों से अपनी परम्परागत डिजाइन एवं विधि से बुनकरी कार्य में संलग्न हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में शत-प्रतिशत कोसा बुनकर कोष्टा जाति के हैं। कोसा वस्त्र बुनकर होने के कारण उनकी जाति का नाम कोष्टा पड़ा है। क्षेत्र के बुनकरों के द्वारा उत्पादित वस्त्र में “कोसा-

साड़ी ” सम्पूर्ण देश में ख्याति प्राप्त है ।

प्रस्तुत अध्ययन में प्रत्यक्ष सर्वेक्षण अनुसंधान पद्धति एवं साक्षात्कार अनुसूची प्रविधि का उपयोग किया गया है । अध्ययन क्षेत्र के 300 बुनकर इकाई परिवार का अध्ययन न्यादर्श रीति से चुनाव कर किया गया है ।

प्रस्तुत अध्ययन प्रदर्शित करता है कि जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ क्षेत्र के कोष्टा समुदाय में बुनकरों की 3 श्रेणी विद्यमान है जिनमें नीजि/ स्वतंत्र बुनकर, महाजन बुनकर एवं सहकारी समिति के बुनकर । क्षेत्र के कोष्टा समुदाय के उच्च शिक्षित व्यक्ति भी अपनी पारम्परिक व्यवसाय को अपनाए हुए हैं । बुनकर 20 वर्ष से बुनाई कार्य आरंभ कर 60 वर्ष की उम्र तक संलग्न रहते हैं । सर्वेक्षण में कहीं-कहीं यह भी देखने को मिला कि 70 वर्ष की उम्र में भी बुनकर बुनाई कार्य कर रहे हैं । बुनकरों से चर्चा में इस बात की जानकारी मिली कि बुनकर परिवार में अधिक आयु का व्यक्ति ही सामान्यतः परिवार का मुखिया हुआ करता है । कोष्टा समुदाय में लघु, मध्यम एवं बड़े आकार के परिवार हैं । जिनमें सदस्यों की संख्या 03 से 17 तक है। कुल 300 प्रतिदर्श बुनकर परिवार में कुल सदस्यों की संख्या 2223 है जिसमें से 1516 (68%) सदस्य बुनाई कार्य में संलग्न है । सर्वे में बुनकर परिवार का औसत सदस्य संख्या 07 पाया गया है । बुनकर परिवार में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का संख्या सर्वाधिक है ।

सर्वे से ज्ञात हुआ है कि अध्ययन क्षेत्र के कोष्टा समुदाय में प्रतिदर्श बुनकरों की शैक्षणिक स्तर में 2% स्नातक एवं उच्च योग्यताधारी हैं, जबकि 75% प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक शिक्षित है एवं 23% पूर्णतः निरक्षर हैं । 63% प्रतिदर्श बुनकर इकाई का आवास कच्चा है एवं 37% बुनकर परिवार का आवास पक्का है । कोष्टा समुदाय की औसत वार्षिक आय 19,000/- रु. है । बुनाई कार्य हेतु बुनकर स्वयं कार्य समय का निर्धारण करते हैं । उनमें कार्य दिवस के औसत घंटे लगभग 10.05 है । वे सप्ताह के सातों दिन व वर्ष भर कार्य में संलग्न रहते हैं । क्षेत्र के अधिकतर बुनकर अपने आवास में कार्य करते हैं ।

इसी प्रकार प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि अध्ययन क्षेत्र के कोष्टा समुदाय के लोगों को स्थायी पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय को दीर्घकाल तक बनाये रखने के लिए होती है जबकि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता उन्हें अल्पकाल के लिए होती है । स्थायी पूंजी का प्रबंध वे स्वयं के साधनों से करते हैं । उनके वित्तीय सहायता प्राप्त करने के स्रोत में महाजन, बैंक, केन्द्र, राज्य सरकार व सहकारी सीमित सहित अन्य स्रोत सम्मिलित है । यह

विशेष उल्लेखनीय है कि क्षेत्र के कोष्टा समुदाय शासकीय सहायता पर आश्रित नहीं रहते हैं। आर्थिक स्थिति का प्रभाव उनके द्वारा निर्मित वस्त्रों के गुणवत्ता एवं मात्रा पर विशेष रूप से पड़ती है तथापि उनके व्यवसायिक अनुभव और व्यक्तिगत शैक्षणिक पृष्ठ भूमि पर भी कपड़ों की गुणवत्ता व मात्रा निर्भर करती है। उनके उपकरण तथा औजार में लगभग एक या दो साधनों को छोड़ कर समस्त साधन जिसे वे बुनकरी कार्य में उपयोग करते हैं वह वृक्षों एवं बांस से बने हुए हैं। सर्वेक्षण में यह स्पष्ट परिलक्षित हुआ है कि वे यंत्र चलित करघा का उपयोग नहीं करते हैं और कोष्टा समुदाय में इन यंत्रों के पीछे आम धारणा यह है कि इसके उपयोग से बुनाई के गुणवत्ता के साथ-साथ उनकी प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है।

कोष्टा समुदाय को बुनाई कला की सीख विरासत में मिली हुई है। सर्वे के दौरान बुनकरों से प्रत्यक्ष चर्चा से प्रतीत हुआ है कि अध्ययन क्षेत्र के बुनकर प्रशिक्षण के संबंध में अल्प ज्ञान रखने वाले शासकीय अधिकारियों की अपेक्षा अपने ही समुदाय के दक्ष कारीगर से सीखने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। उनकी बुनाई प्रक्रिया में कुकिंग, सिटिंग, कताई, रंगाई, ताना बनाना, ताना को बुनाई योग्य करना, बाना बनाना और बाबीन में लपेटना इन सभी कृत्य के बाद वस्त्र तैयार किया जाना शामिल है। वे बाजार के मांग के अनुरूप वस्त्र तैयार करते हैं तथा प्रायः वे महाजनों तथा सहकारी संस्थाओं से कच्चा माल प्राप्त करते हैं। निजि बुनकर महाजन से हुए पूर्व समझौते के अनुसार निर्धारित दरों पर तैयार वस्त्र को बिक्री करते हैं तथा अधिकतर बुनकरों को उत्पाद के बिक्री के लिए बाहर जाने का मौका कम मिलता है। बुनकरों के उत्पाद के विपणन हेतु कोई संगठित बाजार नहीं है फिर भी वे अपने उत्पाद का विक्रय खानदानी पेशेवर व्यापारी, वस्त्र व्यवसायियों तथा मध्यस्थों के जरिये करते हैं।

ग्रामीण समुदाय की सूचना आवश्यकताएं की प्रकृति को समझने के लिए भारत में व्यवस्थित अध्ययन पद्धति का आभाव है। निःसंदेह ग्रामीण समुदाय की सूचना आवश्यकताएं की जानकारी में अंतरनिष्ठ कठिनाइयां हैं साथ ही इसके पहचान हेतु एक भी तकनीक या उपयोग विधि निर्दिष्ट नहीं है। काफी अध्ययन और विश्लेषण के बाद सही तकनीकों एवं विधियों को निश्चित किया जा सकता है। ग्रामीण पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों पर एन. आई. आर. डी. हैदराबाद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वर्कशॉप (9/11सित., 1998)में ग्रामीण सूचना आवश्यकताएं की पहचान आधारीय, आर्थिक, सूचना, शैक्षणिक एवं मनोरंजन आवश्यकताएं के रूप में की गई थी। रायगढ़ क्षेत्रीय कोष्टा समुदाय की सूचना आवश्यकताओं, उन्हें प्राप्त करने के श्रोत

एवं सूचना प्राप्त करने में होने वाली कठिनाईयों से संबंधित जानकारी ज्ञात करने के लिए उनके बुनाई व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को सुनिश्चित करके उन पर समक एकत्रित किये गये ।

सर्वेक्षण से ज्ञात समंको के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि रायगढ़ क्षेत्रीय कोष्टा समुदाय अपने बुनाई व्यवसाय के लिए कच्चा माल एवं शासकीय सहायता के बारे में सर्वाधिक सूचना आवश्यकताएं प्राप्त करना चाहते हैं । इसके बाद क्रमशः बाजार मांग, बुनाई प्रशिक्षण, रूपांकन, उत्पाद का विक्रय स्रोत, रंगाई, उपकरण तथा औजार, निर्यात, प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण, कैमबन्ध, विज्ञापन, एकस्व तथा धागा कटाई पर उन्हें सूचना की आवश्यकताएं हैं । अपनी सूचना आवश्यकताओं हेतु अध्ययन क्षेत्र के कोष्टा समुदाय सूचना प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत के रूप में समूह परिचर्चा पर निर्भर करते हैं । वित्त एजेंसियों से सलाह, प्रशिक्षण शालाओं में उपस्थिति के द्वारा, सरकारी कार्यालयों से, विज्ञापनों के द्वारा, साहित्य अवलोकन से तथा पुस्तकालय भ्रमण क्रमशः कोष्टा समुदाय के सूचना प्राप्त करने के स्रोत के रूप में विद्यमान है । इन लोगों को कच्चा माल, बाजार मांग, शासकीय सहायता तथा उपकरण और औजार सहित अन्य संबंधित पहलुओं पर अपने व्यवसाय को चलाने में कठिनाईयां आती है ।

पुस्तकालय की भूमिका के बारे में सर्वेक्षित आंकड़ों से स्पष्ट उद्घाटित हुआ है कि रायगढ़ क्षेत्रीय कोष्टा समुदाय में पुस्तकालय चेतना का अभाव है । केवल 13% बुनकर जानते हैं कि पुस्तकालय क्या है ? 98% बुनकर सूचना प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं यदि पुस्तकालय उनके क्षेत्र में स्थित हो तो । मात्र 9% बुनकर ग्रंथालय स्थापना हेतु शासन से मांग करने वालों में सम्मिलित हैं एवं 95% बुनकर अपने रूचीगत क्षेत्र में पुस्तकालय सेवा स्वीकारने की इच्छा रखते हैं तथापि 80% बुनकर सशुल्क पुस्तकालय सेवा स्वीकार करने हेतु सहमत हैं ।

निष्कर्ष

राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में सूचना की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। विकसित और विकासशील दोनों ही तरह के देशों में अब सूचना प्रधान समुदाय के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। सूचना प्रधान समुदाय की एक अन्य विशेषता है सूचना क्षेत्र का विकास। डाटा यानी आंकड़ों की पहचान तथा उनका संग्रह तो सूचना उपलब्ध कराने की दिशा में पहला कदम है। अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने और तेजी से फैलते अंतर्राष्ट्रीय सूचना बाजार में भागीदारी हासिल करने के लिए आज देश में स्वदेशी सूचना उद्योग के विकास को जोरदार बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में विज्ञान, टेक्नोलॉजी, औषधि विज्ञान, कला, संस्कृति, वस्तुशिल्प और मानविकी जैसे क्षेत्रों में विस्तृत ज्ञान उपलब्ध है। सूचनायें इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के अलावा भौतिक नेटवर्क जैसे पुस्तकालयों, पुस्तक विक्रेताओं, प्रसारण कम्पनीयों और इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचनायें बेचने वाले संगठनों (जैसे सी. डी. रॉम, डी. वी. डी. पर उपलब्ध डाटा बेस), आई.आई.टी. के माध्यम से भी उपलब्ध करायी जा सकती हैं। सूचनाओं का व्यापक प्रसार भरोसे मंद और मजबूत नेटवर्क की उपलब्धता पर निर्भर है और इस तरह की प्रणाली कायम होने से बेहतर दर्जे की शिक्षा उपलब्ध करायी जा सकेगी, आज का मजबूत आधार बनेगा और अनुसंधान करने वालों तथा उपभोक्ताओं की सूचनाओं तक पहुंच आसान हो सकेगी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के साधनों के समुचित उपयोग द्वारा जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाने, उत्पादन बढ़ाने और समाज के सभी वर्गों के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने आदि की दृष्टि से योजना आयोग गठित की गई थी। आज जबकि नौवीं पंचवर्षीय योजनायें पूरी हो चुकी हैं और दसवीं योजना पर कार्य प्रारंभ है, मूल बात गंभीरता से विचार करने की यह है कि आयोजन जिन लोगों के लिए विशेष रूप से हैं, वे लोग उससे कितने लाभान्वित हुए हैं। इतने वर्षों के विकास की इस यात्रा में देखने में यह आया है कि गरीब और अधिक गरीब हो गया है तथा विकास के परिणामों के फलस्वरूप धन का केन्द्रीयकरण बढ़ा जिससे धनवान और अधिक धनवान हो गया है। यह सही है कि गरीब और अमीर के बीच का मध्यम वर्ग भी इस विकास से लाभान्वित हुआ है। सारांश यह है कि विकास के फल का जिस वर्ग को सबसे पहले पहुंचना चाहिये था, वह या तो अछूता रह गया या फिर उसे सबसे कम लाभ मिला। इसी से आवश्यकता अब इस बात की है कि हम विकास की पूरी अवधारणा पर पुनः विचार

करते हुए उसे स्पष्ट करें। विकास किसका ? विकास किस क्रम में ? और विकास किस कीमत पर ? ऐसे सभी प्रश्नों पर विचार किया जाना चाहिए और विकास की पूरी अवधारणा को सुस्पष्ट सामने रखते हुए भावी नियोजन का कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिये। यथार्थ यह है कि विकास संकेतों से ही आर्थिक सुधारों को नहीं आंका जा सकता, बल्कि जनता की खुशहाली ही इसका पैमाना है इसलिए वास्तविक मूल्यांकन सामाजिक आधार पर ही किया जा सकता है।

देश की अर्थ व्यवस्था में हाथकरघा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह अनेक आर्थिक कार्य-कलापों में से एक है, जो कि बुनाई और अन्य संबंधित गतिविधियों से जुड़े हुए 65 लाख से अधिक लोगों को सीधे रोजगार प्रदान करता है। देश में बनने वाले कुल कपड़ों का लगभग 19% इस क्षेत्र में बनता है तथा निर्यात से होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से प्राप्त होता है। हाथकरघा भारत की विरासत का एक हिस्सा है और देश की समृद्धि और विविधता और बुनकरों की कलाकारी का एक अनुपम उदाहरण है। हाथ से बुने कपड़ों का प्रयोग करने और नवीनताओं को प्रोत्साहित करने की संभावनाओं के कारण हाथकरघा की विविधता अतुलनीय है।

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ क्षेत्र के बुनकर समुदाय (कोष्टा) की हाथकरघा कुटीर उद्योग अपना सुखद अतीत लिए हुए है। उच्च कलात्मक तकनीक और लोकप्रियता के केन्द्र बिन्दु अध्ययन क्षेत्र के कोष्टा समुदाय विविध समस्याओं के बावजूद अपने परंपरागत व्यवसाय को जीवन्त बनाए हुए हैं जो इनके जीवन निर्वाह का एक मात्र प्रमुख साधन है। सर्वेक्षित समूहों के विश्लेषण के आधार पर बुनकर परिवार का औसत वार्षिक आय 19000/- रु. है जबकि कोष्टा परिवार में औसत सदस्य संख्या 07 है। इस प्रकार प्रति सदस्य की औसत वार्षिक आय 2714.28/- रु. तथा मासिक 226.19 रु. है अर्थात् अध्ययन क्षेत्र के कोष्टा समुदाय (बुनकर) गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। क्षेत्र के अधिकतर बुनकर पूंजी के अभाव में महाजनों के अधीन कार्य करने के लिए मजबूर हैं और महाजनों के शोषण के शिकार हैं। क्षेत्र में बुनकर सहकारी समिति स्थापित होने के बाद भी बुनकर समिति में काम करना नापसंद करते हैं। उनके कार्य दशायेँ औसत रूप से अपर्याप्त व अनुपयुक्त है। उनके श्रम के अनुपात में उनकी आय न्यूनतम होती है फलस्वरूप वे अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते हैं।

अध्ययन क्षेत्र के कोष्टा समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में न तो सुधार हुआ है और न ही अधिक खराब हुई है अर्थात् पूर्ववत् स्थिर है। कोष्टा समुदाय में औसत शिक्षा

का स्तर निम्न है फलस्वरूप उनमें पुस्तकालय चेतना की कमी है तथापि वे समाज में पुस्तकालय की भूमिका के बारे में अनभिज्ञ हैं। फिर भी वे क्षेत्र में या स्थानीय स्तर पर पुस्तकालय सेवा प्राप्त करने के इच्छुक हैं और विशेष उल्लेखनीय यह है कि अध्ययन क्षेत्र के कोष्ठा समुदाय पुस्तकालय सेवा को सशुल्क स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं।

कोष्ठा समुदाय के सूचना प्राप्त करने के स्रोत में अनौपचारिक स्रोत पर वे आश्रित हैं तथा इनमें भी समुह परिचर्चा पर वे अधिकतर निर्भर रहते हैं। अध्ययन क्षेत्र के बुनकरों को बुनाई व्यवसाय से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सूचना की आवश्यकता महसूस होती है। विशेषकर उन्हें कच्चा माल, शासकीय सहायता, बाजार मांग, रूपांकन इत्यादि पर सर्वाधिक सूचना आवश्यकताएं हैं। इसी प्रकार वे शासकीय वित्तीय व अनुदान की मदद से उपभोक्ताओं के नवीनतम मांग का सामना करना चाहते हैं। निम्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि व अज्ञानता के कारण कोष्ठा समुदाय के बुनकरों में परस्पर समन्वय का अभाव है।

अध्ययन क्षेत्र के बुनकर जिन बुनियादी समस्याओं से ग्रसित हैं उनमें कच्चे माल की समस्या, उत्पादन एवं विपणन में समन्वय की समस्या, शिक्षा एवं उचित प्रशिक्षण की समस्या, तकनीकी ज्ञान की समस्या वित्तीय समस्या, कार्य दशाओं की समस्या एवं प्रबंध व नियंत्रण की समस्या मुख्य है। इसके अतिरिक्त उत्पाद तथा डिजाईनों में नवीनता का न होना, अभिकल्प, रंगाई व छपाई, अच्छे किस्म के रंगों और छोटे पैक में रसायनों का न मिलना, गुणवत्ता व अनुसंधान को उन्नत बनाना, बुनाई और संसाधन के क्षेत्र में कौशल उन्नत न बनाया जाना भी इस क्षेत्र की बुनियादी कठिनाईयों में शामिल है।

स्वाध्याय की सुविधा की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य काफी पिछड़ा हुआ है। समृद्ध पुस्तकालयों की वह संरचना हमारे राज्य के ग्रामीण अंचलों में अभी तक नहीं हो सकी है और यही कारण है कि ग्रामीण समाज शिक्षा के गुणात्मक मूल्यांकन की दृष्टि से अभी भी काफी पीछे हैं। पुस्तकालयों का महत्व एवं इसकी आवश्यकता किसी से छुपी नहीं है। पुस्तकालय हमारे प्रजातंत्रीय समाज के सूचक हैं जहां बिना किसी भेदभाव तथा जाति, धर्म, आयु के लोग पुस्तकालय के ज्ञान भण्डारों का उपयोग कर सकते हैं। पुस्तकालय आधुनिक परिवर्तनशील युग में चुनौती भरे जीवन को सुगम बनाने में सहायक हैं। मानव के जीवकोउपार्जन की बढ़ती हुई आवश्यकताओं हेतु होने वाले नित्य नये अनुसंधानों और अविष्कारों ने ज्ञान को असीमित बना दिया है, ऐसे में पुस्तकालयों के स्वरूप में बदलाव आता जा रहा है।

कोष्टा समुदाय की आर्थिक स्थिति कमजोर है शिक्षा का विकास नहीं होने के कारण मालूम नहीं चलता है कि उनके कल्याण में कौन-कौन सी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई हैं और उनसे वे कैसे लाभ उठा सकते हैं। अतः इन समुदाय के बीच जाकर उनको इस बात की विश्वास दिलाने और उनका दिल जीतने की आवश्यकता है कि पुस्तकालय ही ज्ञान हासिल करने का सबसे कुशल तरीका है। उनमें पुस्तकालय इस्तेमाल करने की संस्कृति उत्पन्न किये जाने की जरूरत है, एक ऐसी संस्कृति जो कि पढ़ने पर निर्भर होती है, यह उनकी अकादमिक उत्कृष्टता के लिए आवश्यक है तथापि कोष्टा समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिये द्वार पहुँच सूचना सेवा उपलब्ध कराया जाना अत्यंत आवश्यक है।

वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकि ने विश्वव्यापी स्तर पर क्रांति पैदा कर दी है और वर्तमान युग को 'सूचना युग' के नाम से संबोधित किया जाता है। सबसे अधिक प्रभाव सूचना वैश्वीकरण का पुस्तकालयों में पड़ा है। सूचना क्रांति के प्रभाव के चलते पुस्तकालय का स्वरूप परिवर्तित होकर परंपरागत के स्थान पर इलेक्ट्रानिक हो गया है, जिससे वर्चुवल लाइब्रेरी की अवधारणा सामने आयी है। लोगों की सूचना के लिए बढ़ती हुई आवश्यकताएं तथा मांगों के संदर्भ में सामुदायिक सूचना सेवा अब अधिकतम लोकप्रिय हो रहा है। प्रत्यक्ष तौर पर छत्तीसगढ़ भी इस बदलते परिवेश से अलग नहीं रह सकता। सार्वजनिक पुस्तकालयों के द्वारा सामुदायिक सूचना का सफलता पूर्वक कार्यान्वयन से जहां ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर को उन्नत करने में सहायता मिलेगी वहीं दूसरी ओर देश के लोकतंत्रीय आधार में सुदृढ़ता हेतु भी सचमुच में हमें सहायता प्राप्त हो सकेगी।

मुझाव

छत्तीसगढ़ कृषि कार्य की प्राधान्यता के साथ ही उपलब्ध खनिज एवं कच्चे माल की प्रचुरता के दृष्टिगत औद्योगिक उन्नति का मजबूत आधार समाहित किये हुए हैं। नवसृजित छत्तीसगढ़ प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कृषि एवं औद्योगिक विकास हेतु यथेष्ट प्रयास किये जायें। प्रयास भी ऐसे होने चाहिए कि ये न सिर्फ अर्थ पैदा करें वरन् निवासीयों को अधिकतम उनके मूल स्थान से बिना विस्थापित किये उन्हें रोजगार व्यवसाय सहज सुलभ हो सकें। ऐसे विकास के लिए महती आवश्यकता है कि उपलब्ध भौगोलिक कच्चे माल को केन्द्र में रखकर स्थानीय कुटीर व लघु उद्योगों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए नियोजित शासकीय प्रयासों को प्रोत्साहित किये जायें।

छत्तीसगढ़ में बुनकरी कला का अपना एक विशिष्ट योगदान है। यद्यपि अभी तक बुनकर समुदाय अपने परंपरागत संसाधनों से ही इस उद्योग में संलग्न है। नवीन तकनीक की अज्ञानता, सहज-सुलभ अनुपलब्धता, निम्न आर्थिक एवं शैक्षिक क्षमता आदि कारणों से पुरातन प्रविधि एवं पद्धति की सहायता से बुनकरी उद्योग में जुड़े लोगों का छत्तीसगढ़ में एक बड़ा आकार है। आर्थिक विकास में इनके योगदान की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जहां यह लोगों को उनके मूल स्थान पर रखते हुए रोजगार व्यवसाय सुलभ करा रहा है, वहीं उनके परिवार की आजीविका का धनोपार्जन का महत्वपूर्ण आधार है। आर्थिक विकास में बुनकर समुदाय के विशिष्ट योगदान के लिए अत्यंत आवश्यक है कि इसे शिक्षण, प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ ही आधुनिक तकनीक को सहज-सुलभ कराया जाये। उत्पादित माल के लिए बाजार की व्यवस्था की जाये।

आर्थिक विकास की एक इकाई के रूप में बुनकरी उद्योग का संरक्षण संवर्धन जहां रोजगार के अवसरों में वृद्धि करेगा वहीं विस्थापन की समस्या से मुक्ति प्रदान करेगा। वृहद पैमाने के उद्योगों पर अवलंबित समाज में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति सहज विद्यमान होती है जिससे विशाल जनसंख्या के जमाव के फलस्वरूप स्थान विशेष पर अनेक समस्याएं आकस्मिक रूप से प्रकट होकर मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर व्यवधान खड़ी कर देती हैं।

बुनकरी कुटीर उद्योग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण लाभ जो कि स्थानीय जन को उसके अपने घर, गांव के आर्थिक निर्भरता के साथ ही परंपरागत शैली में पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय के शिक्षण-प्रशिक्षण का सहज अवसर भी उपलब्ध कराना है। इससे नयी पीढ़ी को पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सकता है कि वह अपने किशोरावस्था से ही व्यवसाय से स्वाभाविक जुड़ाव बना सके।

आज की एक विभत्स समस्या जो कि प्रत्येक शिक्षित युवक के सामने विकराल रूप में उपस्थित है, वह है रोजगार प्राप्त करने की। बुनकर समुदाय का यह कुटीर उद्योग उसकी नयी पीढ़ी को इस त्रासदी से बिना विशेष प्रयास व अतिरिक्त लागत के ही निजात दिलाने में सक्षम है। इस योगदान से बुनकर समुदाय न सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को अनावश्यक भटकाव व तनाव से मुक्ति दिलायेगा वरन् राष्ट्र व राज्य के कर्तव्य पालन में रोजगार के अवसर का सृजन भी करेगा। व्यक्ति-व्यक्ति के रोजगार संपृक्त होने से परिवार, गांव, राज्य के आत्म निर्भरता भी उसके आर्थिक विकास के पायदान सहज-सुलभ हो सकेंगे। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए अत्यंत आवश्यक है कि मानव संसाधन पर आधारित उद्योग व्यवसायों का प्रचुरता के साथ, नयी तकनीक के साथ, विकेंद्रीकरण के साथ परिष्कार किया जाये। प्रचुर मानव श्रम की उपलब्धता वाले राष्ट्र के लिए विशेष रूप से मशीन आधारित उद्योग ज्यादा लाभप्रद नहीं हो सकते क्योंकि इससे जन के रोजगार की समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ क्षेत्र के कोष्टा समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार, उनकी सूचना आवश्यकताएं और विविध समस्याओं के निराकरण हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत हैं :-

हाथकरघा के बारे में संसद की स्थायी समिति की कपड़ा उप समिति के द्वारा अनुशंसित नीतियों के अनुक्रम में शासन हाथकरघा क्षेत्र को पर्याप्त वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए ताकि बुनकरों का विकास हो और वे बाजार में होड़ कर सकें। निजी तथा सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वालों की सब्सिडी के रूप में सीधे वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सरकार द्वारा मुख्य रूप से तकनीकी कुशलता, टेक्नालॉजी को उन्नत बनाने, विदेशी मंडियों में निर्यात और उसके बारे में जानकारी हासिल करने के उपायों के लिए वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

हमारे घरेलू उद्योग के समक्ष आने वाला समय अत्यंत नाजुक एवं कष्टदायी हो सकता है क्योंकि विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुसार सन् 2004 के पश्चात बहु-तंतु संधि के अधीन मात्रात्मक प्रतिबंध हटने के साथ ही घरेलू बाजार में आयातित कपड़ों की बहुतायत हो जायेगी। भारत में उत्पादकता का स्तर निम्न होने के कारण अब विदेशी बाजार के साथ-साथ घरेलू बाजार में भी नयी चुनौतियां अवश्यसंभावी हैं। अतः बदलते हुए परिवेश का मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर सशक्त नीति तैयार कर कारगर ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया

जाये। इनमें हथकरघा क्षेत्र को केन्द्रीय तथा राज्य करों से मुक्त रखा जाना चाहिए। शासन स्तर पर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें धागों, रंगों, रसायनों तथा अन्य कच्चे माल को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा जाये।

सरकार को चाहिए कि बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्रों के लिए विपणन व्यवस्था में सुधार, विपणन परिसर के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण के लिए बेहतर आयोजन करे। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के अधीन विपणन और निर्यात संवर्धन के लिये स्थापित विपणन परिसर की शाखाएं अध्ययन क्षेत्र में स्थापित किया जावे ताकि रायगढ़ क्षेत्रीय बुनकर समुदाय अपनी कार्यक्षमता में अनिश्चय को दूर करने के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक दशा के प्रति निश्चित हो सकें। इसी प्रकार बुनकरों को स्वास्थ्य पैकेज योजनान्तर्गत तपेदिक और श्वास प्रणाली में दोष, आंखों की जांच और चश्मों, पीने के पानी की आपूर्ति, महिला बुनकरों को प्रभूति लाभ, परिवार नियोजन के स्थायी उपायों के वास्ते अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाये।

राज्य में भारतीय हस्तकरघा टेक्नोलॉजी संस्थान का केन्द्र चाम्पा में स्थापित की जानी चाहिये। उन्नत बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र एवं बुनकर सेवा केन्द्र क्रमशः चांपा एवं चन्द्रपुर में खोला जाना चाहिये। उत्पादन लागत में वृद्धि, मांग में कमी, कार्यशील पूंजी का अभाव, निरंतर बढ़ती महंगाई, करों में वृद्धि, मजदूरों में असंतोष, प्रतिद्वंद्विता, उन्नत प्रौद्योगिकी की कमी, यातायात के साधनों का अभाव, उद्योग, वित्तीय संस्थान एवं डिजाइनर समूह में समन्वय का अभाव आदि चुनौतियों के सामाधान का प्रयास शासन स्तर पर होना चाहिये। विभाग के फील्ड आफिसरों, बुनकर सेवकों एवं बुनकर समिति के तकनीकी कर्मचारियों को बाहर प्रशिक्षण हेतु नियमित रूप से भेजने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार प्रदेश के सभी अभियांत्रिकी एवं बहुशिल्पी महाविद्यालयों में कपड़ा प्रौद्योगिकी का पाठ्यक्रम शासन को प्रारंभ करना चाहिये।

शासन द्वारा प्रदेश के सभी शासकीय विभागों को निर्देश दिया जाना चाहिये कि वे टेबल क्लथ, पर्दा क्लथ, मेडिकल चादर, वर्दी आदि की खरीदी बुनकर सहकारी समितियों से करें। इसी तरह प्राकृतिक विपदाओं पर सुखा राहत कार्य में लगे मजदूरों को नगद भुगतान व चांवल के साथ-साथ हस्तकरघा द्वारा उत्पादित वस्त्रों का उचित दरों पर वितरण शासन स्तर पर सुनिश्चित करवाया जाना चाहिए।

कोष्टा समुदाय के द्वारा उत्पादित वस्त्रों के अधिक प्रचार-प्रसार व विक्रय हेतु शासन को चाहिये कि राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय हथकरघा वस्त्र प्रदर्शनी व व्यापार मेला का

आयोजन एक निश्चित समयावधि में करें। हस्तकरघा विकास आयुक्त की विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में अध्ययन क्षेत्र के बुनकरों को जागरूक बनाने के लिये राज्य स्तरीय कार्यशालाओं, गोष्ठियों, और सम्मेलनों का आयोजन सरकार को करना चाहिए।

राज्य में हाथकरघा सूचना तंत्र स्थापित किया जावे ताकि बुनकरों को अपनी सूचना आवश्यकताओं के लिये किसी अन्य स्रोतों पर आश्रित न रहना पड़े। इससे वे भटकाव से बच सकेंगे साथ ही उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि आयेगी। कोषा समुदाय की हाथकरघा से संबंधित सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्हें द्वार पहुँच सूचना सेवा उपलब्ध कराने के लिये पुस्तकालय सह सूचना केन्द्र की स्थापना किया जाये और इस हेतु सुझाये गये प्रस्ताव का क्रियान्वयन शासन स्तर पर किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

राज्य में पुस्तकालय सेवा को बेहतर बनाने के लिए शासन को सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम शीघ्र पासकर लागू करना चाहिये। जिला स्तर पर सामुदायिक शोध केन्द्र की स्थापना होनी चाहिए।

इसी प्रकार ग्रामीण समुदाय की सूचना की नियमित जरूरतों को पूरा करने के लिये एवं समुदाय आधारित सूचना सेवा उपलब्ध कराने के लिए शासन को पुस्तकालय सह सूचना केन्द्र पंचायत स्तर पर प्रारंभ किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त अध्ययन सामुदायिक सूचना सेवा के ढांचा बनाने वालों को, योजनाकारों को, सूचना नियोजन से संबद्ध व्यक्तियों को निःसंदेह ग्रामीण हस्तकरघा उद्योग के विकास के लिये सामुदायिक सूचना तंत्र को प्रभावी बनाने की दिशा में सहायक होगी।

PROPOSED LIBRARY CUM INFORMATION CENTRE
TO MEET THE KOSTA INFORMATION NEEDS
AND REQUIREMENTS

VARIOUS INFORMATION CENTRES / AGENCIES

- INDIAN INST. OF HAND. TECH.
- WEAVERS SERVICE CENTRE
MINISTRY OF TEXTILES
- TASAR RESEARCH INFORMATION CENTRE
- NIRD LIBRARY
- CREATION OF NATIONAL DATABASE FOR RURAL TECHNOLOGY
- DEST. LIBRARY CUM INFORMATION CENTRE
- DIST. NIC. CENTRE
- DEPTT. OF RURAL INDUSTRIES DEV.
- DIRECTORATE OF HANDLOOM
- RADIO/T.V. CENTRE
- BLOCK LIBRARY INFORMATION CENTRE

COM
MUNI
CAT
ION
NET
WORK

MODERN PANCHAYAT LIBRARY CUM INFORMATION CENTRE

SUB
JECT
AR
EA

USERS NEEDS

- RAW MATERIALS
- FINANCIAL
- MARKETING
- LOOM UPGRADATION & DESIGN INNOVATION
- GOVT. ADDS & GRANTS
- HEALTH & EDUCATION
- QUALITY CONTROL
- DEVELOPMENTS IN NEW WEAVING TECH.
- EXHIBITION/SALE INFORMATION

संभावनाएं

पुस्तकालयों में लोगों की रूची बहुत बढ़ी है और हमारी धारणा यह है कि बौद्धिक जीवन के महत्व तथा ज्ञान के मूल्यों में लोगों का विश्वास दृढ़ हुआ है। आज पुस्तकालय को स्वस्थ मनोरंजन साहित्य उपलब्ध करवाने का ही साधन नहीं माना जाता, बल्कि इसे अब राष्ट्रीय कल्याण की महान संभावनाओं की प्रेरक शक्ति तथा शिक्षा एवं संस्कृति की प्रगति में मूल आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है।

कंप्यूटरों की खोज और सूचना प्रौद्योगिकी का विकास बीसवीं शताब्दी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। प्रगति और विकास के साधन के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका व्यापक रूप से स्वीकार की गई है। उम्मीद है इसके प्रयोग से मानव को बड़े सामाजिक और आर्थिक लाभ होंगे तथा विकास की प्रक्रिया में तेजी आयेगी।

यह बात आज और भी शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है कि सूचना प्रौद्योगिकी सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, बशर्ते कि उसका इस्तेमाल कुशल और कारगर ढंग से किया जाए।

कोई भी गांव एक सटी हुई इकाई होती है जहां विभिन्न माध्यमों- व्यक्तियों की आपसी बातचीत अथवा ग्राम सभाओं और समुदायों के अंदर अनौपचारिक संवाद- समूहों के माध्यम से सूचना का प्रसार होता है। गांव के अंदर सूचना का आदान-प्रदान तेजी से होता है। इंटरनेट विश्व में सभी समुदायों से संबद्ध मामलों पर विचार-विमर्श के माध्यम या मन्च के रूप में सारी दुनिया में सूचना का कारगर प्रसारक बन सकता है और विश्व गांव की स्थापना में सहायक हो सकता है।

इस समय जबकि संचार क्रांति से समूचा विश्व एक गांव के माफिक हो गया है तथा सूचना के संदर्भ में समय और दूरी अब कोई व्यवधान नहीं है ऐसे “ग्लोबल विलेज” वाले जमाने में अब सब कुछ गांव वालों की पहुंच के हद में है। संचार क्रांति की इसी आगाज को शासन के द्वारा पंचायत मुख्यालयों तक पहुंच सुनिश्चित किये जाने पर पंचायत राज की सफलता, बेहतर प्रशासन, स्वावलंबी प्रवृत्ति तथा संसाधन आधारित आदर्श नियोजन में यह सूचना तकनीक क्रांतिकारी उत्प्रेरक का काम करेगी। इंटरनेट तथा उससे जुड़ी प्रौद्योगिकियों के सामने आने से तो एक सर्वथा नया वातावरण नये छत्तीसगढ़ राज्य में बनेगा जिसे सरकार को भविष्य की अधोसंरचना के अनुरूप “इलेक्ट्रानिक-प्रशासन” बनाना होगा।

छत्तीसगढ़ में सूचना प्रबंध के लिये रणनीति तैयार करते समय पंचायतों की भूमिका को सर्वोपरि स्थान दिया जाना चाहिये क्योंकि किसी भी समाज में विकास की अवधारणा एकांगी ही होगी यदि गांव को विकास की मुख्य धारा से न जोड़ा जाये। वैसे सूचना एवं संचार क्रांति का अंतिम लक्ष्य जनकल्याण है और इस दृष्टि से भी जब तक इस क्रांति का लाभ सुदूर गांव तक नहीं पहुंचाया जायेगा यह प्रगति निरर्थक होगी।

पूर्व वर्णित सुझावों के आधार पर यदि शासन द्वारा पुस्तकालय सह सूचना केन्द्र की स्थापना राज्य के ग्रामीण अंचलों में की जाती है तो निम्नांकित प्रबल संभावनायें उल्लेखनीय हैं-

भौगोलिक दूरी एवं सूचना तक अपर्याप्त पहुंच की वजह से गांवों की जो समस्या होती है, ये पुस्तकालय सह सूचना केन्द्र में उनका समाधान करने की सक्षमताएं विद्यमान होगी। इन पुस्तकालय सह सूचना केन्द्रों की परिकल्पना ऐसे सेवा केन्द्रों के रूप में की गई है जो ग्रामीण विकास से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र जैसे -स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, भूमि सुधार, रोजगार के अवसर और संचार में ग्रामीण समुदायों को सेवा उपलब्ध करायेंगे। इनका लक्ष्य ग्रामीण समुदाय की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ एक अति सक्रिय समस्या-समाधान वर्ग के रूप में कार्य करना भी है। यह केन्द्र ग्रामीण समुदायों को ऐसे स्थान और अवसर उपलब्ध कराते हैं जहां वे अपनी जरूरतों, समस्याओं और अपने समाधान आपस में कहते सुनते हैं। इस तरह ये केन्द्र सामुदायिक विकास में बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही शासन की और विश्व समुदाय के साथ संचार सूत्र का कार्य करते हैं।

ग्रामीण समुदाय की नियमित आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा ये केन्द्र स्थानीय स्तर की योजना के लिये एक सूचना आधार का निर्माण भी करते हैं। पुस्तकालय सह सूचना केन्द्र गांव के भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं की रूपरेखा का कंप्यूटर पर डाटाबेस तैयार कर सकेंगे। पंचायत एवं विकासखंड स्तरों पर स्थानीय प्रशासक भी इन केन्द्रों के संसाधनों के उपयोगकर्ता होंगे। ये पुस्तकालय सह सूचना केन्द्र निम्न सक्षमताएं रखेंगे:-

- 1- गांव के अपूर्ण शिक्षित बच्चों एवं युवकों के शिक्षा को तरो-ताजा रखने में मदद करना जिसे उन्होंने अपनी पढ़ाई और प्रशिक्षण के दौरान हासिल किया।
- 2- ग्रामीण व्यक्ति को पुस्तकों, पत्रिकाओं, पाम्पलेट्स इत्यादि के उपयोगिता, मनोरंजन के लिए चलचित्र, कल्पनाओं और भावनाओं की वृद्धि में सहायता प्रदान करना।
- 3- शासन के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं विकास योजनाओं की जानकारी रखना।

इस प्रकार इस जानकारी के जरिये लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार के मामलों में परामर्श एवं मार्गदर्शन देना ।

- 4- प्रशासन में पारदर्शिता एवं लोगों को सभी प्रकार की सूचना सहज रूप में प्रदान करना जो अन्यथा आम समुदाय से छुपी रहती है ।
 - 5- कृषि विस्तारीकरण, स्वास्थ्य से जुड़े एवं अन्य जागरूकता उत्पन्न करने वाले कार्यक्रमों के क्षेत्र में शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए मल्टीमिडिया सुविधाएं प्रदान करना ।
 - 6- भूमि सुधार प्रबंधन, कृषि कारोबार, जनस्वास्थ्य स्तर के लिये डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली और प्रबंध सूचना प्रणाली ।
 - 7- समुदाय को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए कम्प्यूटर साक्षरता प्रदान करना ।
 - 8- समुदाय के सभी सदस्यों को समान रूप से निःशुल्क सेवा प्रदान करना ।
 - 9- सभी निष्पादित कलाओं के सांस्कृतिक अभिव्यक्ति हेतु अभिगमन व्यवस्थित करना तथा अंतर्सांस्कृतिक संवाद को विकसीत करना ।
 - 10- सामाजिक- आर्थिक विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले ग्राम स्तर के सामुदायिक संगठनों, ग्राम पंचायतों एवं सर्वेच्छिक संगठनों की आवश्यकताओं को संबोधित करना।
 - 11- हमारे कृषकों के कार्य की कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायता, खाद्य और भूमि की उर्वरता, कृषि उपज एवं विपणन, पशुधन, उत्पादकों और उपभोक्ताओं में सहयोग की भावनायें, बढ़ाईगिरी, कृषि कारीगर, कृषि के मौलिक यंत्रकला, फसल सुरक्षा बीमा की जानकारी सुलभ कराने के साथ- साथ कृषि जलवायु में परिवर्तन पर डाटाबेस ।
 - 12- विकास कार्यक्रमों का प्रभावी प्रबंधन एवं स्थानीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार करना जिससे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की गति तेज हो सके ।
 - 13- स्थानीय शासन में समुदायों की भूमिका बढ़ाना एवं उनका सशक्तिकरण करना ।
 - 14- जहां भी संचार सुविधाएं उपलब्ध हो वहां “इंटरनेट” की सुविधा प्रदान करना । इस प्रकार वैश्विक समुदाय की एक खिड़की के रूप में कार्य करना ।
- प्रत्येक पुस्तकालय सह सूचना केन्द्र के विशेष सूचना संसाधन उस ग्रामों के ग्रामीण समुदाय की सूचना की आवश्यकताओं के मुताबिक भिन्न-भिन्न होंगे ।